श्री रामेश्वर सिंह : तो अखबारों में सारी बातें नहीं आयीं । मैंने कल भी कहा था कि अखबार तो पूंजीपतियों के है और वह सही बात नहीं छापते । बहुत सी बातें छिपा रखते हैं । लेकिन आप देखिए कि छपरा से ट्रेन आ रही थी . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : उसको आप छोड़ दीजिए . . . (व्यवधान)

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Is it the policy of the Leader of the House to field two types of teams? One is the female team to tackle the male. Whenever he wants the male to be attacked, he fields the female. Whenever men like Rameshwar Singh speak these females. . . (*Interruptions*). We have to be very careful. You have to protect us because it is not only happening inside the House but in the lobby also. . . (*Interruptions*). Now I would also request Rameshwar Singh to concluded. मैं भी कुछ कांट्रीब्यूट करना चाहता हू । तो इसलिए रामेश्वर सिंह जी, आप कम्प्लीट करिए ।

SHRI N. K. P. SALVE: I will make three categories. There are three categories. One is male, the second is female and the third Rameshwar Singh. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will continue it after half-an-hour discussion is over in the evening. (*Interruptions*).

श्री रामेश्वर सिंह : मैं क्या क्या करूं ? इसको आप रोकिए । इस सबको तो आप ही रोक सकते हैं । मेरा क्या कसूर है । . . . (व्यवधान) आप इजाजत दीजिए कि जो मैं बोलूं वह रेकार्ड हो जाये ।

श्री उपसभापति : अब आप कितना समय और लेंगे ?

श्री रामेश्वर सिंह : मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा । दो मिनट में खत्म कर दूंगा ।

श्री उपसभापति : आप तीन मिनट ले लीजिए । आपने दो मिनट मांगे हैं, मैं तीन मिनट देता हू । आप इसमे समाप्त करिए ।

श्री रामेश्वर सिंह : तो श्रीमन, देखिए कि ट्रेन आ रही थी छपरा से . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : मुझे लगता है कि आप लोग नहीं चाहते कि यह कालिंग अटेंशन लंच के पहले समाप्त हो । इसलिए यह कालिंग अटेंशन हाफ ऐन हावर डिसकशन के बाद लिया जाएगा और इसके बाद सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at fifty-eight minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

THE BIHAR ATOMIC AUTHORITY BILL, 1978—contd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, further consideration of the Bihar Atomic Authority Bill,, 1978—**Shri** Hukmdeo Narayan Yadav.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मैं एक बात कहना चाहता हूं । मुझे इस पर बोलना नहीं है ।

श्री उपसभापति: आप तो बोल चुके हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : इतना ही कहना है कि यह विधेयक बहुत गम्भीर है । बिहार में अटोमिक अथोरिटी खोलने की मांग मैंने इस बिल में उठाई है । बिहार पिछड़ा

(श्री शिव चन्द्र झा)

प्रदेश है इसी दृष्टिकोण से यह बहुत जरूरी है . . .

श्री उपसभापति : आप सब कह चुके हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : इनको बोलने दीजिए।

श्री शिव चन्द्र झा : यूरेनियम के लिये हमें दूसरी कंटरी के मोहताज होना पड़ता है। (व्यवधा) मैं यह चाहूंगा कि जो मंत्री जी अभी बैठे हैं वह बैठे रहें, लेकिन जब सब बातें खत्म हो जाएं तब अच्छा होगा यदि प्रधान मंत्री जी आकर स्वयं उत्तर दें।

श्री उपसभापति : मंत्री जी बैठे हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं चाहूंगा प्रधान मंत्री जी आकर जवाब दें और यह बतायें कि कब तक अटोमिक अथोरिटी खोलने का विचार है और इसका सर्वे कब तक होगा।

श्री उपसभापति : रिप्लाई में आप यह सब बातें कह देना।

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : हमारे रिप्लाई में आपका सेटिसफेक्शन हो जाएगा। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री हुक्म देव नारायण यादव (बिहार) : उपसभापति जी, मैं शिव चन्द्र झा जी को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि वह बिहार के विकास के लिये एक गैर-सरकारी विधेयक इस सदन में लाए हैं और इससे भी ज्यादा सरकार को तब बधाई दूंगा जब वह इस विधेयक को स्वीकार कर लेंगे। वैसे तो सरकारी विधेयक को तो आप पास करा ही लेते हैं अगर एक-आध गैर-सरकारी विधेयक भी पास करा दें; क्योंकि संख्या आपके पास है और अपनी संख्या के बल पर पास करा दें, तो आपका कोई नुक्सान होगा नहीं बल्कि बिहार की जनता में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको यश मिलेगा, लाभ मिलेगा। वैसे भी बिहार में आपकी सरकार है। यह भी नहीं होगा कि कोई विरोधी दल यह कह सकेगा कि हम इसके हिस्सेदार हैं। 16 आने यश आपको ही मिलेगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को सरकार अपना विधेयक मान ले। सरकारी विधेयक मानकर इसको पास करा दे।

मेरी यह प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में बहुत आबादी है। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर और बिहार जो हैं वे इतनी आबादी रखते हुए अभागे प्रदेश माने गये हैं। न तो वहां कोई कारखाना है और आर्थिक विकास भी वहां नहीं हुआ है। इन मामलों में वह पिछड़ा ही रहा है। अकाल और बाढ़ से भी हर साल दबे रहते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि इन पिछड़े हुए इलाकों में ज्यादा सुविधा मिले। दुनिया में भी एक सिद्धांत चला है कि पिछड़े हुए देश के लिये जो दुनिया के आर्थिक संस्थान हैं वे उनकी विशेष सुविधा के लिये मांग करते हैं तो देश के अन्दर जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनको भी विशेष सुविधा देने की बात की जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग इत्यादि लगाने पर ध्यान देना चाहिये जिससे वहां विकास हो सके। एक तो वहां आबादी ज्यादा है और लोग भी खेती पर ज्यादातर निर्भर रहते हैं। खेती से पेट भी नहीं भर रहा है। हमारे पास जमीन है, हमारे पास पानी भी है, सब कुछ है लेकिन हम

पिछड़े हैं इसका क्या कारण है। वहां कोई उद्योग नहीं है। जहां मैंने झा जी को धन्यवाद दिया वहां दूसरी तरफ मुझे दुख भी है कि झा जी जो अटोमिक कारखाना बनवाना चाहते हैं वह भी गंगा के दक्षिण में ले जाना चाहते हैं। जहां कुछ तो है लेकिन उत्तर बिहार जो सबसे पिछड़ा इलाका है जहां कुछ भी सुलभ नहीं है वहां खोलने की बात नहीं करते हैं। एक अशोक पेपर मिल थी वह भी नहीं चल रही है। ठाकुर पेपर मिल थी वह भी नहीं चल रही है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। अभी झा जी ने जो विधेयक पेश किया है उनमें उन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं। आज जब दुनिया अणु के क्षेत्र में प्रगति कर रही है और अणु के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही और अणु के माध्यम से दुनिया प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रही है तो जब बिहार में इतना ज्यादा यूरेनियम मिल रहा है तो उसका उपयोग बिहार में भी किया जाना चाहिए। आप उस पूरे यूरेनियम को बन्द करके दूसरी जगहों पर भेज देते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर परिष्कृत यूरेनियम बिहार में इस्तेमाल किया जाय और उसके लिए परमाणु संयंत्र लगाया जाये तो इससे बिहार के लोगों को लाभ होगा। इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरे प्रान्तों के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। यूरेनियम को बिहार से दूसरे जगहों पर ले जाने में खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो आप हिन्दुस्तान के कई स्थानों पर इस प्रकार के संयंत्र बना रहे हैं और कई जगहों पर उद्योग भी स्थापित कर रहे हैं। ऐसी हालत में यह बात समझ में नहीं आती है कि आप बिहार में इस प्रकार का संयंत्र क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप जानते हैं कि बिहार में कोयले के भंडार हैं। इसके अलावा बिहार में दूसरे खनिज-पदार्थ भी काफी मात्रा में मिलते हैं। कौन सी चीज ऐसी है जो बिहार में नहीं मिलती है। फिर भी दुनिया में यह कितने आश्चर्य की बात है कि जिस प्रदेश की धरती के नीचे सबसे अधिक सम्पत्ति है वह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। दुनिया में इस प्रकार की चीजों को देखने वाला इसको आठवां या नवां आश्चर्य ही समझेगा। जिस प्रदेश में यह परमाणु संयंत्र लगाने के लिए विधेयक लाया गया है वह आदिवासियों का, दबे हुए लोगों का, जंगलों में रहने वाले बन-वासियों का इलाका है। इन स्थानों पर जब उद्योग लगाये गये तो इन पिछड़े हुए लोगों की जमीन छीन ली गई। लेकिन इन कारखानों में इन लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। मैं यह नहीं कहता कि हिन्दुस्तान के दूसरे लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सब गरीब लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की जमीन छीन ली गई, जिनके पास जीवन को चलाने का कोई दूसरा साधन नहीं है उनको इन कारखानों में रोजगार दिया जाना चाहिए। आप उनकी जमीन एक हजार या दो हजार में खरीद लेते हैं, लेकिन उनको इन कारखानों में रोजगार नहीं देते हैं। एक हजार या दो हजार में जमीन खरीद कर उसी जमीन को 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार और 30 हजार में बेच देते हैं। जिन लोगों की जमीन छीनी जाती है उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। उस जमीन से होने वाली आय में भी उन लोगों को हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि जिन लोगों की जमीन कारखाने लगाने के लिए छीनी जाती है उनको इन कारखानों में किस प्रकार से रोजगार दिया जाये

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

और उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाये।

श्रीमन्, मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारी बात अखबारों में छपे या न छपे मैं दुनिया को आगाह कर देना चाहता हूं भारत को आगाह कर देना चाहता हू और इस सदन के माध्यम से हिन्दुस्तान के लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के पूर्वांचल मे, उर्वशीयम में आग की जो लपट चल रही है उसी तरह से लपटें बिहार के दक्षिण भाग, बिहार के संथाल क्षेत्रों में और छोटा नागपुर के इलाकों में भी चल रही हैं। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो संथाल, परगना और छोटा नागपुर के क्षेत्रों से चलने वाली ये लपटें यू० पी०, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा बंगाल में भी फैल जाएंगी। यह इस तरह की बीच में आग लग चुकी है। क्यों? इसके बारे में अभी आप सोचें। क्योंकि अगर उनको दबा देने के लिए आप यह कानून बना दे कि उस इलाके में बसने वाले लोगों को तीर धनुष लेकर नहीं चलने देंगे तो ठीक है आदिवासियों ने कहा कि हमें अगर तीर धनुष नहीं उठाने दोगे तो भगवान राम के चित्र से तीर धनुष हटा दो। हमारे अवतार भगवान राम हमेशा तीर धनुष लेकर चलते थे। आखिर हमारे सामने मजबूरी है और उस मजबूरी में हम हथियार उठा रहे हैं, मजबूरी में हम लड़ रहे है, मजबूरी में जान दे रहे हैं, हमारे सामने मजबूरी है। मैं तो यह चाहूंगा कि दक्षिणी बिहार और बिहार के पिछड़े इलाकों के अन्दर जो क्रान्ति की ज्वाला फूट पड़ी है इससे सरकार सचेत और सावधान अगर समय रहते न हो पायेगी तो सरकार के लिए कुछ करना असम्भव और कठिन हो जायेगा। इसलिए समय रहते सरकार को चेत जाना चाहिए और उस इलाके की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उपसभापति महोदय, सरकारी अफसरों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे उनकी समस्या का हल निकाल सकें वह इसलिए कि छोटा नागपुर और संथाल परगना में ऐसे दबे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, जंगलों में बसने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो उन इलाकों में जो आफिसर भी जाते हैं उन आफिसरों का बर्ताव, उन आफिसरों का सम्बन्ध उन गरीबों के साथ ऐसा रहता है जैसा कि अंग्रेज आफिसरों का सम्बन्ध भी उनके साथ नहीं रहता था। और वे आफिसर जो वहां जाते हैं वे उनका शोषण करते हैं और वे उनको इस तरह से दबा कर रखते हैं और इस तरह से पैरों के तले रखते हैं जिसकी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, जिसकी सभ्य युग में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंसान को कोठरी में जानवरों जैसे बन्द करके रखा जाता है और उनसे मनमाने ढंग से मजदूरी कराई जाती है। आज भी बिहार के उन इलाकों में इस तरह की प्रथा चल रही है। एक-एक आदमी चाहे दस-दस लड़कियों, बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस औरतों को जैसा चाहे अपने कब्जे में रखता है। आज वहां पर इस तरह की बातें चल रही हैं। गरीबी से मजबूर इंसान, जहां आदमी निराश भी है और निराश्रित भी है, उसे अगर प्रशासन के जरिए और सामाजिक परिवर्तन के जरिए कोई आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ेगी तो फिर उसके सामने मरता क्या न करता, वह हथियार भी उठा सकता है, वह हिंसात्मक आन्दोलन भी शुरू कर सकता है और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए खून देना भी आदमी पसंद करता है। आज उनके लिए न केवल रोटी का ही

सवाल है बल्कि रोटी के साथ-साथ उनकी इज्जत का भी सवाल है । मैं इसको राजनैतिक विषय नहीं मानता लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि जब कभी बिहार के अन्दर वोट लेने का सवाल आता है तो राजनैनिक दल लोगों से कहलवाकर ऐसे लोगों के नाम अखबार में छपवाना शुरू कर देते हैं जिनके जरिए उन्हें वोट मिलें कि अगर विरोधी पक्ष का होगा तो कैसा होगा और सत्ताधारी पक्ष का होगा तो कैसा होगा । मैंने देखा कि जब विधान सभा का चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव के पहले अखबारों में यह शाया किया जाता था कि बिहार में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो कौन मुख्य मंत्री बनेगा । सवाल होते थे और उत्तर होता था कि सीताराम केसरी बनने वाले हैं, भीष्म नारायण सिंह बनने वाले हैं, कोई यादव भी बनने वाले हैं, कोई फलाना बनने वाला है । चुनाव हो गया और सरकार बनने का जब मौका आया तो झा झा मेल दरभंगा से खुलकर दिल्ली पहुंच गई और झा झा मेल के अलावा दूसरी मेल पटरी पर चल ही नहीं सकती । केवल एक मेल है झा झा मेल । कोई इधर से आया कोई उधर से आया परन्तु वहां झा झा मेल ही चलेगी । तो मैं यह कह रहा हूं कि जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शोषण हमारा हो रहा है उस आर्थिक, मामाजिक और राजनैतिक शोषण को भी हम देखने का काम करें । केवल वहां नहीं हम बिहार से जब यहां आकर दिल्ली में अपनी छवि आईने में देखते हैं तो हमारी आंखें फटी रह जाती हैं और हमें यहां भी वही देखने को मिलता है । बिहार के लिए और उस इलाके के लिए हम यहां यह मानने लगे हैं कि वहां दूसरे लोग बसने वाले है ही नहीं । इसलिए आप लोगों को इस पर भी सोचना चाहिए कि इनका उससे कोई नुकसान नहीं है । ये दबे हुए लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग, जिन्हें समाज के अन्दर हजारों-लाखों-करोड़ों वर्षों से आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक तौर पर दबा कर रखा गया है उनको उठाने के लिए अगर आप काम करते हैं तो उससे आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी और वोट भी बढ़ेगा । इससे आपका नुकसान क्या होगा ? हम कभी-कभी ऐसी बात बोलते हैं जिसके कारण हमें नुकसान होता है और उससे क्या होता है कि वोट उस ओर चला जाता है । हम तो बोलते हैं मगर शुद्ध विरोध पक्ष को जो बात कहनी चाहिए वही सोच कर कहते हैं । हमारी नियत केवल विरोध करने की नहीं है हम आपको उचित मंत्रणा देंगे । हम जितना ही आपका विरोध नहीं करेंगे आप उतने ही निकम्मे बने रहेंगे और इससे आपसे ज्यादा हमारा काम होगा, उससे उतना ही ज्यादा हमारा संगठन बढ़ेगा । लेकिन हम इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको सुझाव देते हैं । आप इन बातों पर गहराई से चलने का काम करें ।

उपसभापति जी, केवल इस अटामिक बिल पर ही नहीं, और भी जो मैंने सवाल उठाये हैं, जिन गरीब आदिवासियों, जंगलों में बसने वाले लोगों का सवाल मैंने आपकी नजर में रखा, मैं चाहता हूं कि सदन उन पर विचार करे । मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार संसद सदस्यों की समिति बनाये और संसदीय समिति का एक शिष्टमण्डल दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर, संथाल परगना इलाकों में जाए और वहां पर जाकर देखे । आप भी जानते होंगे कि उत्तर बिहार के कुछ नामी-गिरामी लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ नामी-गिरामी लोग, बलिया, बस्ती, गोरखपुर के लोग उन

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव

आदिवासी इलाकों में चले गए हैं। आज वे सामन्त महाराज से भी ज्यादा खतरनाक बन गए हैं। उनके पास में अपने 100 नहीं हजारों लठैत हैं। उन लठैतों के बल पर सरकारी खानों में चाहे जितना कोयला चोरी कर लें, बोकारो के स्टील प्लांट में से चाहे जितना लोहा चुरा ले जाएं जैसे भी चाहें लेकिन उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि उनका राजनीतिक प्रभाव सब के ऊपर है। मैंने जनता पार्टी की सरकार भी देखी, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी मैंने देखी है। मैंने देखा यह लाठी चलाने वाले लोग, बदमाशी करने वाले लोग, दबा कर रखने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग किसी न किसी तरह से सभी दलों के साथ कोई न कोई सूत्र या संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसलिए यह शोषण चल रहा है, उसके लिए संसदीय समिति बनावें और वहां जाकर पूरी जांच करा लें तब जा कर आपको असलियत का पता लगेगा कि वहां क्या अन्याय हो रहा है। हमारे बिहार के पूर्णिया जिले में, सहरसा जिले में, कटिहार जिले में चले जाइये। इन इलाकों में जूट काफी पैदा होता है। अकेले कटिहार में हमारी जूट फैक्टरी थी और वह भी बन्द है और सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। बीमार मिलों को तो सरकार ले लेती है लेकिन बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री कार्पुरी ठाकुर जी कहा करते थे कि सरकार कोई अस्पताल नहीं है जो बीमार मिलों को ले ले। जब केन्द्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी और बिहार में कार्पुरी ठाकुर जी की सरकार थी उस समय 16 बीमार चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का सवाल आया था तब कार्पुरी ठाकुर ने कहा कि तन्दुरुस्त मिलें तो पूंजीपति चलावें तथा सरकार कोई अस्पताल नहीं है जो बीमार मिलों को लेती जाए। कटिहार जूट मिल जब बीमार थी तो सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया आज वहां पर भी उत्पात मचा हुआ है। हमारे समाजवादी आन्दोलन के जबर्दस्त नेता, गरीबों के लिए लड़ने वाले भूतपूर्व सांसद युवराज जिसको बिहार और उत्तर प्रदेश का हर समाजवादी जानता है, आज उन मजदूरों के सवाल को लेकर अनशन पर बैठे हैं तथा जेल में डाल दिए गए हैं। जेल में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनको पटना अस्पताल में भर्ती किया गया। जितने नेता हैं सभी नेताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि युवराज के इलाज की बात सरकार करे, उनको रिहा करने की बात करे। न तो उनको रिहा किया गया और न उनको छोड़ा जा रहा है न उनका इलाज किया जा रहा है। मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो एटोमिक के बारे में विधेयक श्री झा जी ने दिया है यह तो केवल यूरेनियम एटोमिक से संबंधित है, प्रान्त के औद्योगीकरण से संबंधित है। इस बिल का मकसद क्या है। हम बिहार में औद्योगिक कारखाने, इंडस्ट्रीज बैठायें और बिहार का औद्योगिकरण करें और उसकी मारफत हमारे यहां की विपुल सम्पदा जो धरती के नीचे छिपी हुई है, जमीन के नीचे जो हमारी दौलत है उनका जो शोषण होता है इसी की बात मैं कहता हूं लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि हमारे यहां जितने कारखाने हैं और जितने हमारे यहां समान निकल रहे हैं, उनके सभी के आफिसेज बाहर बनाये गए हैं। कारखाना बिहार में, उत्पादन बहार में, हैड आफिस कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में और बम्बई में रखे गए हैं। इससे लगभग 14-15 सौ करोड़ रुपये हमारे जो बिहार को टैक्स के रूप में मिलने चाहिएं वह पैसा मारा जाता है। यह पैसा दूसरे प्रान्तों में चला जाता है। हमारी समग्र बातों को दृष्टि में रख कर इंडस्ट्रीज बैठाने के समय, हम जो भी कारखाने बैठाते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, उसकी मारफत हम लोगों को कुछ रोजी दे सकें, रोजगार दे सकें और रोजगार देकर वहां के

जो पिछड़े हुए लोग हैं, शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ा सकें उनको ताकतवर बना सकें, उनको खुशहाल बना सकें। इसलिए मैं सरकार को तब धन्यवाद दूंगा, ज्यादा धन्यवाद दूंगा और आपके हित में भी है, जो विधेयक उन्होंने पेश किया है अगर आप पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका मानस पिछड़े क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है, आपका मानस आर्थिक असंतुलन को दूर करना है, सामाजिक असंतुलन को दूर करना है, राजनीतिक असंतुलन को दूर करना है, समाज के अन्दर जो बेकार लोग हैं उनको रोजी और रोजगार देना है, किसानों को ऊपर उठाना है, खेती के साथ-साथ उनको कोई और रोजगार देना है तो आप यह कारखाने बैठायें और बैठायेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी प्रशंसा होगी। दोनों जगह, दिल्ली और बिहार में आपकी ही सरकार है और कारखाना बनाने से आपकी ही प्रशंसा होगी, हमारी सरकार तो बिहार में है नहीं कि आपके यश में कुछ हिस्सा बटायेंगे और कुछ नाम कमाने के लिए हम भी कहेंगे कि इसके करवाने में हमारा हाथ था। अत: आप सोलहों आने मन से इस काम को करिये, निष्पक्ष भाव से करिये, उदार बनकर करिये और जो शिव चन्द्र झा जी ने विधेयक पेश किया है यह साधु विधेयक है इसमें जंजाल झगड़ा नहीं है। आपको इस काम को करना ही चाहिए। तो मैं आशा और विश्वास के साथ श्री झा जी के विधेयक का समर्थन करता हूं कि बिहार जैसे पिछड़े इलाके में आप इस कारखाने के अलावा और कारखाने खोलिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और कारखानों को बैठाईये जिससे वह इलाका विकसित हो सके और खुशहाल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) : उपसभापति जी, हमारे मित्र श्री शिव चन्द्र झा जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसकी हृदय से ताईद करता हूं, समर्थन करता हूं, मैं आपका समय नहीं लूंगा। उन्होंने अपनी बातें कह दी हैं। हमारे दोस्त श्री हुक्म देव जी ने काफी बातें कह दी हैं। यह जो आपका जादूगुडा का एरिया है, जमशेदपुर से निकलकर जादूगुड़ा का इलाका है, वहां यूरेनियम की तमाम रिच बेल्ट्स हैं। हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया का सेंटर भी है लेकिन इस बिल का जो उद्देश्य है कि बिहार में एटामिक अथारिटी कायम होनी चाहिए, मैं इसके साथ हूं। यह ठीक है कि गवर्नमेंट इसकी जांच करेगी। लेकिन स्पिरिट के साथ हम लोगों का ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को यह अवसर मिलेगा कि वह सभी तरह से जांच करे। प्रस्ताव पर भी गवर्नमेंट जांच करे फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जवाब होगा परन्तु ऐसा मेरा ख्याल है कि इस चीज को कर दिया जाय तो हम बिहार के लोगों को बहुत संतोष होगा। यश जिसको मिले, केसरी जी को मिले, मंत्री जी को मिले जगन्नाथ मिश्रा जी को मिले, हम कहते हैं इन्हीं को मिले। लेकिन मुझे इस पर इतना ही कहना है और गम्भीरता पूर्वक बड़ी सेंसिबिलिटी के साथ रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस पर विचार करे और कोशिश करे कि यह काम, झा जी ने जो विधेयक पेश किया है उसके चलते ही हो जाय, जिससे बिहार वासियों को संतोष हो कि हां गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हमारी तरफ ध्यान दिया गया है। धीरे-धीरे ये चीजें नोटिस में आती हैं, मैं भी गवर्नमेंट में था, नहीं हो सका यह काम। ये लोग बहुत से काम नहीं कर सकते लेकिन जैसे जैसे इस प्रकार की चीजें नोटिस में आती हैं उनको निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से करना चाहिए चूंकि यह जनहित का

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

काम है । बिहार का काम है । इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं, आपने समय दिया इसका मैं शुक्रगुजार हूं और मैं पूरे हृदय के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : उपसभापति जी, मैं शिव चन्द्र झा जी ने जो प्रस्ताव लाया है उसका समर्थन करता हूं । शायद यह पहला समय है कि समझ-बूझ का प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य शिव चन्द्र झा जी ने लाया है । यह कांस्ट्रक्टिव सुझाव झा जी का है और वे भी बड़े खुश हैं कि इस प्रस्ताव पर चारों तरफ से लोगों की सहमती मिल रही है ।

उपसभापति जी, आप जानते हैं कि बिहार राज्य खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है इसमें हर तरह के खनिज पदार्थ हैं दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बिहार की जमीन के अन्दर न हो। ऊपर भी पैदावार के मामले जैसे जहां तक अनाज और दूसरी चीजों की बात है खाने की चीजों की, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि शिव चन्द्र झा जी के गुरू श्री लोहिया जी ने कहा था कि बिहार की भूमि सोना उगलने वाली भूमि है। तो जमीन के अन्दर से भी सोना और ऊपर से भी सोना उगलने वाली जमीन है। लेकिन बिहार राज्य की अपेक्षा बड़े ही पैमाने पर, कोई भी सरकार हुई हो सदा से करती चली आयी है । हमें दुःख है कि कांग्रेस राज्य की तो कुछ उपलब्धियां मिली कुछ कल कारखाने बने इंडस्ट्रीलाइजेशन बिहार का हुआ जैसे हटिया बना, बोकारो बना और दूसरे प्लांट बने लेकिन जनता पार्टी का जब राज्य हुआ तो एक भी कल कारखाना नहीं बन सका ।
3P.M. और यह आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि यूरेनियम जो काफी बहुमूल्य है, स्केयर्स है और स्ट्रैटेजिक मैटीरियल है, इसकी इलीगल माइनिंग करके जनता पार्टी के राज्य में काफी मात्रा में नेपाल होकर के चीन गया । इसकी रिपोर्टस आई, अखबारों में छपा कि यह मैटीरियल --यह चमकता हुआ यूरेनियम होता है, कास्टली होता है, इसकी लोग इलीगल माईनिंग करते हैं और जैसे श्री हुक्मदेव नारायण जी ने कहा, बिलकुल सही कहा, जब बिहार गवर्नमेंन्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, तो कोई सुनवाई जनता पार्टी के टाइम में नहीं हुई ।

मुझे याद है कि एक बार कांग्रेस की रिजीम में भी इस प्रकार की घटना हुई, श्री कृष्णबल्लभ बाबू उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, हम लोग उस समय बिहार एसेम्बली में मेम्बर थे-- immediately he rushed in the evening by his own car to Hazaribagh. went to the spot and ordered—

उन्होंने आर्डर दिया कि सारे एरिया को कार्डन करो और जो व्यवस्था की गई थी युरेनियम की इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, यह स्ट्रैटेजिक मैटीरियल कहीं दूसरी जगह न जा सके, वह सारा तोड़ दिया गया, खत्म हो गया । आज ओपन है कोई भी निकालता है, छेटी में लेकर के चला जाता है । उठायेगा और लेकर कहीं भी चला जायेगा । ऐसे-ऐसे मैटीरियल वहां मिलते हैं देहातों में --आप चले जाइये, सिंहभूमि में चले जाइये--रास्ते मे जा रहे हैं, आप देखेंगे कि कापर का हिल ऊपर निकला हुआ है । शहर में, देहात में, गांव में चले जाइये, कहीं देखेंगे कि सड़क पर उंचा उठा हुआ टीला है और वह कापर है । यह स्थिति में सिंहभूमि की-- कितने अच्छे खनिज पदार्थ वहां है ।

तो यह यूरेनियम पर बेस्ड प्लांट बनना चाहिए, इसलिए भी कि जो बाहर का सामान चाहिए इस प्लांट को बनाने के लिए, सारा बिहार राज्य में उपलब्ध है। जो इंडस्ट्रियल बाहरी जरूरत है इसको बनाने के लिए, जैसे कोयला उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, रेल हैड्स और मैटेरियल प्रचुर मात्रा में है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, मैन पावर सस्ता है, चीप है। मैन पावर जो है, काफी चीप है, वह भी मंहगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं और वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हैं। मदर आफ इंडस्ट्रीज हटिया है—जो प्लांट में रिक्वायर्ड मशीनरी होगी, उस को वह दे सकता है। ऐसी हालत में जो मांग श्री शिव चन्द्र झा जी ने की है, वह ठीक है।

भारत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस सम्बन्ध में एक विधेयक ला करके जो आज यूरेनियम की लूट हो गयी है, स्मगल हो रहा है वहां से, बाहर जा रहा है, इलीगल माइनिंग लोग कर रहे हैं, कोयले के ट्रक में नीचे यूरेनियम रहता है और ऊपर कोयला रहता है और प्राइवेट कन्ट्रेक्टर्स या दूसरे कोयले के नाम पर उसको लेकर चले जाते हैं, बंगला देश चले जायेंगे, नेपाल चले जायेंगे, सरहद पार जायेगा, नेपाल जायेगा और वहां से चीन जायेगा।

तो इस स्केयर्स मैटेरियल को सेव करने के लिए वहां अगर प्लांट हो जाता है, तो काफी सस्ता भी पड़ेगा। आप यूरेनियम यहां से ले जायें, कोटा से ले जायें या दूसरी जगह से ले जायें तो वह कास्टली पड़ता है। इस लिए भी हमें चाहिए कि क्योंकि वह चीपैस्ट पड़ेगा हर मामले में उस का वहां बनना जरूरी है।

लेकिन दुख की बात तो यह है कि बिहार की उपेक्षा बराबर इस मामले में की गई है। जहां तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है। अभी वहल गांव में एक थर्मल पावर पलांट बनना था। परन्तु जनता पार्टी के रिजीम में उसे बंगाल ट्रांसफर कर दिया गया और कहां चला गया—फरक्का ब्रिज के पास। उसको बनना था वहलगांव में—उससे हमें बिजली मिलती। हमारे यहां लघु उद्योग काफी संख्या में है और क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, एंसिलरी इंडस्ट्री है, लघु उद्योग काफी हैं उनके लिए बिजली चाहिए और आज वह थर्मल पावर प्लांट बना दें तो हमारे नार्थ बिहार का जो हिस्सा है, केवल एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री एक भी नहीं है, उसको कुछ बिजली उसे मिलती तो वह लघु उद्योग शुरू कर सकते थे उत्तर बिहार में। आप को सुन कर ताज्जुब होगा, हमारे प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर हम लोगों ने कई बार इस पार्लयामैन्ट में और बिहार की असेम्बली में भी, यह प्रश्न उठाया कि शिवान जिस भूमि में वे पैदा हुए थे वहां कोई एक इंडस्ट्री कायम कर दीजिए, एक युनिवर्सिटी वहां कायम कर दीजिए लेकिन कोई चीज अभी तक कायम नहीं की। जब जार्ज फर्नान्डीज भारत सरकार के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो बिहार के सभी संसद्-सदस्यों को उन्होंने बुलाया। मैंने इस प्रस्ताव को रखा कि आप एक काम कर दीजिए कि शिवान में एच एम टी की एक ब्रांच खोल दीजिए भलेही आप राजेन्द्र बाबू के नाम पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं दे सकते। इस सिंहभूमि में, आप को सुन कर ताज्जुब हुआ—जहां राजेन्द्र बाबू पैदा हुए थे—उस इलाके में एक वर्ग मील में 4400 लोग रहते हैं,

[श्री रामानन्द यादव]

जबकि जर्मनी यूरोप में सब से घना है, 600 आदमी वर्गमील रहते हैं, दरभंगा में 2300 आदमी रहते हैं और 4400 आदमी उस शिवान इलाके में हैं। हिन्दुस्तान का सबसे बडा गांव उस इलाके का है जिस में 10 पोलिंग बूथ हैं, क्या कोई इमेजिन कर सकता है कितनी डेन्सली पापुलेटेड है, जहां की 6 धूरा जमीन प्रति व्यक्ति पड़ती है। हमने कहा कि यह बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है नार्थ बिहार का, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हो, कुछ इंडस्ट्री कायम करने की कोशिश करो। थर्मल पावर का प्लांट ही दिया गया है, हम लोगों ने कहा जल्दी से जल्दी वैगंस कोयले के और दूसरी चीजें मोहैय्या कीजिये ताकि वहां थर्मल पावर बन जाये, और फिर दूसरी इंडस्ट्री बन जायें। घड़ी के कारखाने का सुझाव हम लोगों ने एक स्वर से दिया था, सभी लोगों ने कहा उस में शिव चन्द्र झा भी थे। सभी ने कहा, शिवान में कोई बडी इंडस्ट्री नहीं दे सकते तो कम से कम एच एम टी की एक ब्रांच घड़ी के पुर्जे असेम्बल करने के लिए खोल दिया जाये। उन्होंने स्वीकार भी किया लेकिन अब सुन रहे हैं कि वह भी इंडस्ट्री उड़ कर चली जा रही है पटना में। शायद आप जानते होंगे, नार्थ बिहार में 28 शूगर फैक्टरियां हैं और बगास जिसको चकवा कहते हैं, शुगर क्रश करने के बाद जो उसका बगास निकलता है जिस को खाल कहते हैं।

(व्यवधान) ... मोलासेज नहीं

u fail to understand the difference 'ween molasses and begasse

बगास होता है वह, नकली वाला मोलास होता है जो कि शुगर बनने के बाद छंटता है। तो वहां पर बगास-बेस्ड इंडस्ट्री खोलने की जरूरत

और एक जापानी टीम भी आई थी, जापानी टीम ने सरवे किया और कहा कि सबसे उपयुक्त जगह शिवान है जहां बगास-बेस्ड एक पेपर फैक्ट्री को खोला जा सकता है। गोरखपुर, देवरिया और बस्ती ये भी शिवान से नजदीक है और वहां भी काफी शुगर फैक्ट्रीज हैं। शिवान, बेतिया, मुजफ्फरपुर इन सब इलाकों में करीब 28 शुगर फैक्टरीज पड़ती हैं। तो यहां पर एक सेल्फ-फीडिंग प्लांट हो सकता है क्योंकि जैसे घास हैं, बांस है या दूसरी चीजें हैं पेपर बनाने में काम आने वाली उनको दूसरी जगह से लाने की आवश्यकता नही पड़ेगी। लेकिन न मालूम क्या कारण है कि नार्थ बिहार में इसकी जरूरत होते हुए भी उसके प्रति कोई भी सरकार होती है उसका ध्यान जाता नही। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कम से कम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आज जरूरी है कि एटामिक बेस्ड प्लाण्ट जादूगुडा में हो और उसके हो जाने से दूसरी एंसिलरी इंडस्ट्री होंगी, इसलिए बिजली भी होगी और दूसरी चीजें भी बनेगी। इस तरह से हमारे बिहार का थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि जितने कारखाने हैं या बड़े-बड़ेउ द्योग-धंधे हैं, और पहले जो कोयले के कारखाने थे, कोयले की खानें थीं, सबों का हैड आफिस या तो कलकत्ता नहीं तो बम्बई में होता था क्योंकि गुजराती भाई अधिकांश कोयले की खाने चलाते थे। इसलिए या तो कलकत्ता में अपना हेड आफिस रखते थे या फिर बम्बई में रखते थे। टाटा का इतना बड़ा प्लान्ट है, दुनिया भर की सम्पत्ति उस ने बिहार की भूमि से, सिंहभूम की भूमि से कमायी, जहां के लोग पिछड़े हैं, भूखे हैं, जहां हर साल अकाल पड़ता है, लाखों की संख्या में लोग बाहर जा कर गुजर करते हैं, उस इलाके से टाटा ने इतना कमाया, लेकिन हेड आफिस कहां लगाया? बम्बई में। मैं चाहूंगा सरकार से– यह इस बिल के बाहर की बात है—कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, जहां कारखाने हैं हैड आफिस वहीं होना चाहिए। यह तो हुई प्राइवेट क्षेत्र की बात। अब मैं सरकारी क्षेत्र की बात करता हूं। आरिजनली जब स्टील अथारिटी बनी तो रांची में उस का हेड आफिस था। बाद में ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर दिल्ली में लाया गया। दिल्ली में हिन्दुस्तान टाइम्स

की बिल्डिंग में उस स्टील अथारिटी का दफ्तर बना। केबिनेट डिसीजन है कि स्टील अथारिटी का दफ्तर बिहार में होगा। जनता पार्टी ने इस बात पर ख्याल नहीं किया। मैं दोषी ठहराता हूं बिजू बाबू को जो उस वक्त स्टील मिनिस्टर थे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रणव बाबू को जिन्होंने यह फैसला लिया है कि स्टील अथारिटी का दफ्तर निश्चित रूप से बिहार जायेगा। उन्होंने आर्डर दे दिया है, लेकिन आफीशियल लेवल पर यह हो रहा है कि यह दफ्तर न जाये। आलरेडी जमीन खरीद ली है, घर बनाना शुरू कर दिया है, जल्दी से जल्दी बन जायं जिस से यह मामला खत्म हो जाय। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रणब जी को, कामर्स मिनिस्टर को, स्टील एंड माइंस मिनिस्टर को कि उन्होंने आफीशियल प्रेशर को न मान कर यह फैसला लिया कि जब केबिनेट डिसीजन है तो उस को मानना होगा। एक बार नहीं, तीन-चार बार भारत सरकार की केबिनेट का डिसीजन हुआ है लेकिन उस को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस तरह बिहार राज्य को आर्थिक मामले में पंगु बनाया जाता है और गरीब रखा जाता है।

इसी तरह कोयले का दफ्तर है, कोल इंडिया का दफ्तर है। सब से अधिक कोयला बिहार में होता है लेकिन कोल इंडिया का दफ्तर कलकत्ते में है। अधिक से अधिक कोयला जिस इलाके में होता है वह है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और बंगाल का रानीगंज का इलाका। चाहिए तो यह था कि कोल इंडिया का दफ्तर रांची में होता जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के मध्य में पड़ता। स्टील अथारिटी का दफ्तर कहां होना? रांची में होना। आप देखिये बोकारो, रूरकेला, भिलाई तीनों बड़े बड़े प्लांट किस बेल्ट में है। उसी हिली ट्रैक्ट के बीच का स्थान रांची है। लेकिन गया कहां? दिल्ली चला आया क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वे यहां बैठ कर सिगार पियेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, मौज करेंगे और रिमोट एरिया से शासन करेंगे। दूसरा यहां से शासन करने का फल क्या होता है? एक मशीनरी खरीदनी होगी, कोई आर्डर लेना होगा तो चार दिन में फाइल मूव करेगी। हाट लाइन इनकी जो लगी हुई है टेलीफोन की वह काम नहीं करती। कई बार मैंने बैठ कर देखा है; कहा है फोन कीजिये तो बताया है कि हाट लाइन खराब है, बात नहीं हो सकेगी। यह स्थिति है। आप किसी भी उद्योग धन्धे के कारखाने के सम्बन्ध में सोचें तो मुझे यही कहना है कि बिहार की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। एटामिक प्लान्ट बनना चाहिए था तो सब से पहले बिहार में बनना चाहिए था, सिंहभूम में बनना चाहिए था, हजारीबाग में बनना चाहिए था जो हिली एरिया है, जहां के लोग सब से गरीब हैं, जहां सब से सस्ते मजदूर मिलते है, स्ट्रेटेजिक पोइन्ट आफ व्यू जो हिन्टरलैंड है। आप समुद्र के किनारे पर प्लान्ट खड़ा कर दीजिये, जब दुश्मन चाहे समुद्री पनडुब्बी से आकर लड़ाई के जमाने में एक मिनट में बम से उसे नष्ट कर देगा। लेकिन हवाई जहाज से आने में उसको कठिनाई होगी। तो यह जो प्लान्ट बनना चाहिए था बिहार में उसे आप ने किसी और दूसरी ऐसी जगह बनाया है कि जहां खर्च भी अधिक पड़ता है माल को ढोकर के ले जाने में और जहां मैन पावर भी अधिक मंहगा है, सस्ता नहीं। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक पर वह ठंडे दिल से विचार करे और यह दूसरी बात है कि यह पास न हो और मैं तो शिवचन्द्र झा जी से कहूंगा कि वे इस को वापस ले लें और सरकार इसके लिये तो आश्वासन दे दे लेकिन फिर सरकार पर दबाव डाल कर कुछ कराये। ऐसा होने से यह काम शीघ्र हो जायगा क्योंकि सरकार की ओर से इस बारे में तो कोई आश्वासन होगा ही कि कोई कार्यवाही की जायगी।

एक माननीय सदस्य : और अगर सरकार न करे तो?

श्री रामानन्द यादव : न करे तो हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और जैसे हम बोलते हैं

[श्री रामानन्द यादव]

बोलते रहेंगे। आज हमारे यहां का जो लेबर है, जो वहां का मजदूर है उस को काम नहीं मिलता। वहां के जो पढ़े लिखे लोग है उन को नौकरियां नही मिलतीं। उनमें भी बेकारों की संख्या बहुत बड़ी हो गयी है। बेपढ़े जो हैं उनकी संख्या तो पता ही नहीं कि कितनी है। वह तो अनगिनत है। उन की कोई इंतिहा नहीं। जिस किसी गांव में आप चले जाइये, जो अशिक्षित प्रौढ़ है, वयस्क है, बालक हैं उनकी काफी संख्या है और ऐसे बहुत से लोग बेरोजगार है। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इंजीनियर्स बेरोजगार है और हिन्दुस्तान में बेकारों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। जो बड़े बड़े कारखाने खुले हैं वहां, उनमें बाहर के लोग आ गये। हटिया मे चले जाइये, बोकारो मे चले जाइये, वहां सब बाहर के लोग नौकरी में हैं। हमारे यहां के लोग तो खेती करते है। वह खेत पर छाता लेकर खड़े रहेंगे और मजदूरों से काम करवाते रहेंगे। अपने हाथ से तो काम करते नहीं और इस लिये बाहर के लोग आये और परिश्रम करके नौकरियों में लग गये। तो इस से आज हमारी बेरोजगारी भी बढ़ गयी है। हमारे यहां छोटा नागपुर के इलाके के लोग जो सब से अधिक बेरोजगार हो गये हैं, भूमिहीन हो गये है वह इस लिये कि उनकी जमीन कारखानों ने ले ली और उनको मुआवजा नहीं दिया गया। बोकारो के विषय में मै जानता हूं कि बोकारो प्लान्ट के लिये जमीन ली गयी है और यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि वह उन लोगों को मुआवजे का पैसा दे। भारत सरकार को वह पैसा देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? वह पैसा दे दिया बिहार सरकार को और बिहार सरकार के सर्वे विभाग के जो लोग हैं, जो पैसा वितरण करते हैं रेवेन्यू विभाग के लोग, वह पैसा नहीं देते। तो आज वहां का आदिवासी रिवोल्ट कर रहा है। वह नौकरी खोजता है। उस की जमीन पर आज उत्तर बिहार के लोग, देवरिया के लोग, बलिया के लोग दखल जमा कर बैठ गये हैं। उसकी नौकरी भी उन लोगों ने ले ली और ठेके भी ले लिये। कोयला चुनने के लिये आपने देखा कि जो गरीब मजदूर आदिवासी कोयला चुनता था टाटा के कारखाने में उस के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया है। नार्थ बिहार के एक ठेकेदार ने 19 आदमियों को पानी में फेंकवा दिया। तो इस तरह से उनका शोषण होता है। इस ज्वाला को आप यदि शान्ति करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इस तरह के प्लान्ट्स वहां बैठा कर साउथ बिहार के लोगों को वहां नौकरी दीजिए ताकि वे शान्त रह सकें और उन को शान्त रखना जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि वहां फारन ऐलिमेंट्स बहुत काम कर रहे है, मिशनरी वहा काम कर रही हैं जो अमरीकी ऐजेन्ट बनकर बैठी हुई हैं उन पर रोक लगाई जाए। आपने देखा कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है। जहां जहां आदिवासी इलाके है मिशनरियों के माध्यम से अमरीकी ऐजेन्ट सक्रिय हैं और एक बैल्ट बनी हुई है उनके पास। आप हर जगह देखिये, पूर्वाचल से लेकर चारों तरफ देख लीजिए, इन्हीं बैल्टों में बराबर विद्रोह की ज्वाला जलाई जाती है, इन मिशनरियों के द्वारा। तो उन्हें शान्त करने के लिए, उनके आक्रमण को निरस्त करने के लिए एक ही उपाय है कि वहां के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, वहां के एरियाज़ को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए नये नये प्लान्ट्स दिये जायें। वहां के लोगों को प्राथमिकता दीजिए ताकि नौकरियां उनको मिल सकें और वहां के लोग अपना जीवन ठीक से निर्वाह कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिवचन्द्र झा जी से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को उठा लेंगे और हम लोग सरकार पर दबाव डालेंगे कि सरकार इस काम को करे ताकि बिहार की भलाई हो सके।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, श्री शिव चन्द्र झा ने जो यहां बिल पेश किया है, 1962 में जो ऐटामिक ऐनर्जी ऐक्ट बनाया भारत सरकार ने, जिसमें कि विकास के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है, उसको देखते हुए इस बिल की कोई जरूरत नहीं है।

उपसभापति महोदय, अभी शिवचन्द्र झा और हमारे साथी रामानन्द जी ने बिहार के पिछड़ेपन की बात कही। आज हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। लेकिन इस अटामिक अथारिटी से पिछड़ेपन का एक रिश्ता है और इसीलिए हमारे देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब हिन्दुस्तान आज़ाद हुआ तो हिन्दुस्तान के विकास के लिए साइंस और टेक्नालाजी को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि हिन्दुस्तान साइंस और टेक्नालाजी में आगे हुआ और इस पालिसी को अडाप्ट करने के बाद आज दुनिया में पांचवां अटामिक पावर बना, दुनिया में छठा स्पेस पावर बना, दुनिया का चौथा फर्टिलाइज़ टेक्नालाजी जानने वाला देश बना, दुनिया का तीसरा टेक्नीकल नो हाऊ वाला पावर बना, दुनियां का आठवां इंडस्ट्रियल पावर बना, दुनिया का छठा अग्रिकल्चरल पावर बना। हमने कृषि और औद्योगिक विकास तथा अपने साइंस और टेक्नालाजी पर चलकर इस विकास की गति को प्राप्त किया। सवाल है एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के विकास का और उसी संदर्भ में भारत के विकास है। आजादी के बाद हिन्दुस्तान ने बहुत विकास किया क्योंकि जो देश राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर चुके है तब भी वे आर्थिक दृष्टि से मज़बूत नही होते वे अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1947 के बाद एशिया और अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र आज़ाद हुए और इन मुल्कों मे जनतांत्रिक पद्धति या जम्हूरियत आई लेकिन एशिया और अफ्रीका के अधिकांश मुल्कों में जनतंत्र का गला घोंटा गया। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें डेमोक्रेटिक तरीके की सरकार पिछले 32 सालों से कायम है और डेमोक्रेटिक तरीके से विकास की तरफ लगातार बढ़ रही है।

उपसभापति महोदय, पिछले 25-30 सालों तक इस मुल्क में कांग्रेस की सरकार रही। उसने साइंस के विकास के लिए प्राथमिकता दी, पंचवर्षीय योजनाओं में। उसने कृषि के विकास के लिए अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में साइंस और टेक्नालाजी को महत्व दिया। लेकिन आदरणीय शिवचन्द्र झा जिस पार्टी के नेता हैं इनकी सरकार जब 1977 में सत्ता में आई तो पहला काम, पहली कैज्यूअल्टी जो जनता सरकार की हुई, जो जनता सरकार ने पहला हमला किया वह साइंस और टेक्नालाजी की पालिसी पर किया और बेशर्मी इस हद तक हुई कि इनकी पार्टी के प्रधान मंत्री अमरीका गये और अमरीका की सैनेट के सामने उन्होंने बयान दिया —

"The most unfortunate act that was done by Mrs. Gandhi was the explosion of atom at Pokaran."

यानी हिन्दुस्तान में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम किया वह था पोखरन में अटामिक विस्फोट का होना। यह वक्तव्य अमरीका की धरती पर श्री मोरारजी देसाई, इस मुल्क के जनता पार्टी के तथाकथित नेता ने दिया।

उपसभापति महोदय, यह वक्तव्य हिन्दुस्तान की आज़ादी का सीधा सौदा था अमरीका से। उन्होने वहां यह स्वीकार किया कि हिन्दुस्तान के अटामिक रिसर्च सेंटर का इंस्पेक्शन भी अमरीकन टीम, वर्ल्ड बैंक की टीम करेगी। उपसभापति महोदय, जिस समय हिन्दुस्तान ने एटम बम का एक्सपलोशन किया, एटम का एक्सपलोशन पोखरन में किया तो सबसे ज्यादा गुस्सा अमेरिका को आया,

[श्री कल्प नाथ राय]

सबसे ज्यादा गुस्सा चाइना को आया और यूरोप के मुल्कों को आया। क्यों? उस समय भारत सरकार के खिलाफ गुस्से का इज़हार किया यूरोप के मुलकों ने। क्यों? उस समय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसी पार्लियामेंट में यह कहा था :

"I do not care for the Americans, I do not care for the Chinese. What I do care for is the people of India. Once India did not join the industrial revolution and that was the reason for the slavery of India. If India will not join the technological revolution, India cannot protect its freedom."

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि हम चाइना और अमेरिका की परवाह नहीं करते, हम परवाह करते हैं अपने भारत देश की। हर हिन्दुस्तानी ने औद्योगिक क्रांति में भाग नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप यूरोप में कारखाने बनाने वाले देशों ने हिन्दुस्तान को गुलाम बना लिया। अगर हिन्दुस्तान तकनीकी क्रांति में भी भाग नहीं लेगा तो हिन्दुस्तान अपनी आजादी की रक्षा नहीं कर सकता। हमने एटम को तोड़ा लड़ाई के लिये नहीं, दवा के लिये। हमने एटम को तोड़ा लड़ाई के लिये नहीं, घर-घर में बिजली पहुंचाने के लिये। हमने एटम को तोड़ा लड़ाई के लिये नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से एशिया और अफ्रीका, भारत के पिछड़े हुए राष्ट्रों के विकास के लिये। हमने एटम को तोड़ा, भारत के हर खेत में पानी पहुंचाने के लिये। हमने एटम तोड़ा, भारत की गरीबी को मिटाने के लिये। हमने एटम को तोड़ा, भारत के विकास के लिये। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1971 में एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। जो लोग गरीबी हटाना चाहते हैं, वे कांग्रेस को वोट देंगे और जो हम को हटाना चाहते हैं वे विरोधी दल को वोट देंगे। मैं आदरणीय साथियों से पूछना चाहता हूं कि गरीबी कैसे हटेगी। हिन्दुस्तान की आबादी 70 करोड़ की है। अमेरिका की आबादी 22 करोड़ है। रूस की आबादी 24 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हिन्दुस्तान से चार गुणा अधिक है। रूस का क्षेत्रफल हिन्दुस्तान से सात गुणा अधिक है। हिन्दुस्तान की आबादी है 70 करोड़। हमने जब हिन्दुस्तान की आजादी हासिल की तो उस समय मुल्क की आबादी 40 करोड़ की थी। इस हिन्दुस्तान की आजादी हमने 1947 में हासिल की थी। उसी की आबादी आज बढ़ कर 70 करोड़ हो गई है। जबकि अमेरिका की 22 करोड़ है। सारी दुनिया को लूटने के बाद, सारी दुनिया का शोषण करने के बाद, पूंजीवादी हथियार से, पूंजीवादी व्यवस्था से सारी दुनिया को लूटने के बाद अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण हुआ। कम्युनिस्ट आईरन कर्टन में जहां कोई बोल नहीं सकता, जहां वाणी की आजादी नहीं है वहां ही 24 करोड़ लोगों के रूस का निर्माण हुआ 64 वर्षों के अन्दर। इन 24 करोड़ लोगों को भी रूस में खाना नहीं मिल रहा है। उन्हें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है। हमने हिन्दुस्तान में फैसला किया कि न हम पूंजीवादी व्यवस्था से अपने देश का निर्माण करेंगे और न समाजवादी तरीके से देश का निर्माण करेंगे। हमें तीसरी फिलासफी लानी होगी। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जनतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है। जिसके अंदर हमने स्वीकार किया कि हम रोटी की आजादी, हम पेट की आजादी देंगे। हम वाणी की आजादी और पेट की आजादी दोनों देंगे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इसी कंस्टीट्यूशन असेम्बली में बैठ कर भारत के संविधान को बनाया था। इसमें भारत को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाने की घोषणा की गई थी। हमें समाजवादी, पूंजीवादी गुदगुदी से हट कर तीसरी दुनिया का निर्माण करना है जिसमें नर को आजादी और पेट की आजादी होगी। इसमें रोटी की आजादी होगी। पिछले 32 सालों से हम वही लड़ाई लड़ते आये हैं। हमारा संविधान भी इसी उद्देश्य

से बनाया गया था कि हमारे देश में सब के साथ समानता का व्यवहार होगा। भारत के अन्दर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का एक्सपेरिमेन्टेशन सफल हुआ है और आज यह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे देश की प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें समाजवाद की हरियाली घाटी में पहुंचने के लिये लम्बा रास्ता तय करना है। यह लम्बा रास्ता तय करने के लिये यह आवश्यक है कि हमे बैकवर्ड इकनोमी से डेवलपिंग इकनोमी की तरफ बढ़ना है। भारत जैसे देश में सारी पार्टियों को विरोधी दलों की पार्टियों को आपस में मिल-जुल कर भारत की समस्याओं का हल ढूंढना होगा। भारत की समस्यायें कैसे हल होंगी, भारत की गरीबी कैसे दूर होगी ये कुछ ऐसे सवाल है जिन पर हम सब को विचार करना है। भारत की गरीबी दूर होगी बिजली से। बिजली कैसे पैदा होती है? बिजली पैदा होती है पानी से ? बिजली पैदा होती है कोयले से, बिजली पैदा होती है एटोमिक एनर्जी से, बिजली पैदा होती है समुद्र की लहरों से, बिजली पैदा होती है सूरज की रोशनी से। इन चीजों से बिजली पैदा होती है। भारत को बिजली की आवश्यकता है। पानी से बिजली बनाना आवश्यक है। भारत में बिजली बनाने की आवश्यकता है कोयले से। आज हिन्दुस्तान में 26 हजार मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है जिसमें से 20 हजार मेगावाट कोयले से पैदा हो रही है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री विश्वम्भर नाथ पांडे) पीठासीन हुए]

6 हजार मेगावाट बिजली पानी से मिल रही है। इस प्रकार से 26 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना है। हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ हमारी मांगें भी बढ़ती जा रही है। 70 करोड़ हजारों वर्षों से गरीब और पिछड़े देशवासियों के लिये बिजली की आवश्यकता होगी। जैसा मैंने कहा बिजली पानी से बनती है, कोयले से बनती है और एटम से बनती है। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इस देश में सबसे पहले एटोमिक कमीशन बना और एटम पर इस देश में रिसर्च हुई। हमने एटम को तोड़ना सीखा। नरौरा मे, उत्तर प्रदेश में एक बिजली का स्टेशन बनाया गया, बड़ौदा में बिजली का स्टेशन बना, महाराष्ट्र के ट्रोम्बे में बिजली का स्टेशन बना, कल्पाकम में बिजली का स्टेशन बना। जब सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उसके प्रधान मंत्री अमेरिका गये। उन्होंने कहा कि हम एटोमिक विस्फोट नहीं करेंगे, श्री मोरारजी देसाई अमेरिका के सामने दांत निपोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे लेकिन अमेरिका ने परिष्कृत यूरेनियम नहीं भेजा, एनरिच्ड यूरेनियम नहीं भेजा। जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने तारापुर के लिये एनरिच्ड यूरेनियम भेज दिया। अपने तीन वर्ष की अवधि में जनता पार्टी की सरकार अमरिका से यूरेनियम नहीं ले सकी। श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता में आते ही अमेरिका ने एनरिच्ड यूरेनियम दे दिया। इंदिरा गांधी ने साफ लिखा है—

> "Those who want to test our courage will find it strong., Those who seek our friendship will find it honourable."

अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे, न दैन्य न पलायनं।

हमने एटम से बिजली पैदा की है और हमने एटम से बिजली पैदा करने की बात सोची है। अपने तीन वर्ष के शासन के दौरान जनता पार्टी ने सारे रिसर्च

[श्री कल्प नाथ राय]

के काम बन्द कर दिये, साइंस और टैक्नोलोजी की नीति को समाप्त कर दिया। हिन्दुस्तान में चल रही एटोमिक रिसर्च को बन्द कर दिया। सी० एस० आई० आर० को बन्द कर दिया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही छठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा देश की जनता के सामने रखा। साइंटिफिक और टैक्नोलोजिकल प्रगति के लिये मार्ग प्रशस्त किया। साइंटिफिक और टैक्नोलोजिकल रिसर्च तथा एटोमिक रिसर्च दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने गरीबी हटाने के लिये नरौरा में, कल्पाकम में, तारापुर में, बड़ौदा में और अन्य स्थानों पर कोटा में बड़े बड़े रिसर्च सेन्टर्स कायम किये हैं। तो गरीबी हटेगी कैसे। यह क्या हुक्मदेव नारायण जी के भाषण से हटेगी क्या यह अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों से हटेगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, गरीबी हटेगी जब भारत अपनी साइंस और टैक्नालाजी की पालिसी पर चलेगा। जब दुनिया के संदर्भ में भारत का क्या रोल होगा इस पर चलेगा हिन्दुस्तान के सारे राजनैतिक दल जब भारत की समस्याओं को समझेंगे और समस्याओं के सवालों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर राष्ट्रीय समस्याओं का हल ढूढेंगे। उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह भूल मत जाइये कि आपने अपनी तीन साल की हुकूमत में केवल चरित्र हत्या की राजनीति अपनाई और अपने विरोधियों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। आपने देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर 28 कमीशन बिठाये और नाना प्रकार के अत्याचार और पापाचार किये। लेकिन तीन वर्ष के बाद जब देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने क्या कहा। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने वही नीति अपनाई होती तो आप जैसे लोगों का आज यहां पता भी नहीं चलता। आपने किस तरह से व्यवहार किया राजा के साथ राजा का सा व्यवहार करना चाहिये। अगर वह देश की प्रधानमंत्री थी उनके साथ राजा के साथ राजा जैसा व्यवहार करना चाहिये था। लेकिन जब देश की नेता इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने देश की जनता का आह्वाहन किया तो उन्होंने देश की जनता से कहा कि हमारे शत्रु वे नहीं है जिन्होंने हमें तीन साल यातनायें दीं। हमारे शत्रु वे नहीं है जिन्होंने हमें सताया है मेरे परिवार को सताया है बल्कि हमारा और आपका शत्रु भारत की गरीबी है। आओ हम मिलजुलकर उस गरीबी को दूर करें और नये आधुनिक विकसित समाजवादी शक्तिशाली हिन्दुस्तान का निर्माण करें। एक आधुनिक विकसित शक्तिशाली समाजवादी भारत का निर्माण कैसे होगा? यह निर्माण तब होगा जब हिन्दुस्तान में पर्याप्त मात्रा में बिजली बनेगी। फिर बिजली कैसे बनेगी? बिजली तब बनेगी जब परमाणु से बिजली बनाना हम सीखेंगे। भारत के पेट में. यूरेनियम और प्लेटेनिम इतना ज्यादा मात्रा में है कि अगर हिन्दुस्तान एटम से बिजली बनाना सीख ले तो आने वाले जमाने में हिन्दुस्तान आज जो अमरीका है वह हो जायेगा और जो आज हिन्दुस्तान है वह अमरीका बन जायेगा। क्योंकि जिस दिन हिन्दुस्तान ऐटम से बिजली बनाना सीख जायेगा, जिस दिन हिन्दुस्तान के हर खेत पर पानी पहुंच जायेगा, हर कारखाने को बिजली मिल जायेगी, हिन्दुस्तान के हर नौजवान को काम मिल जायेगा, उस दिन हिन्दुस्तान आधुनिक विकसित शक्तिशाली देश बन जायेगा। यह काम तभी होगा जब ऐटम से बिजली बनाना हम सीख जायेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, अमरीका और यूरोप के मुल्क क्या चाहते हैं? वे यह चाहते हैं

कि हिन्दुस्तान एक रा-मैटीरियल सप्लाई करने वाला देश बना रहे और अमरीका और यूरोप के मुल्क फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई वाले देश बने रहें और हिन्दुस्तान उनका एक मार्केट बना रहे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसका शुरू से विरोध किया था और 1947 से नेहरू जो कहते आये कि हमें सेल्फ रेलायन्ट एकानामी, आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए ताकि भारत अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। हमारा अमेरिका से कोई विरोध नहीं है। विरोध जो है वह है नीतियों का। अमेरिका और युरोप के मुल्क चाहते हैं कि हिन्दुस्तान एक रा-मैटिरियल सप्लाई कन्ट्री बना रहे और, हम फिनिश्ड गुड्स उसको देते रहें। पंडित जवाहर लाल नेहरु शुरू से ही चाहते थे कि हिन्दुस्तान साइंस ऐंड टेक्नालाजी की नीति को अपना कर अपनी एक सेल्फ रेलायन्ट एकानामी का निर्माण करे ताकि हम अपने पैरों पर, आत्मनिर्भर हो सकें और एशिया तथा अफ्रीका के देशों को साम्राज्यवाद के शोषण से बचायें। उपसभाध्यक्ष महोदय, हम रूस को धन्यवाद इसलिए देते है कि रूस ने पब्लिक सेक्टर में हमें कारखाने लगाने में मदद की, रूस ने हमारे लोहे के कारखाने बनाने में मदद दी, रूस ने हमें हैवी इंजीनियरिंग कारखानों को बनाने में हमारी मदद की, रूस ने हिन्दुस्तान को अपनी सेल्फ रेलायन्ट एकनामी को बिल्ट अप करने में मदद की इसीलिए हम उसके दोस्त हैं। अमेरिका ने शुरू से हिन्दुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा न होने पाये और वह सदैव हमारा मार्केट बना रहे, इस बात की कोशिश की। इसलिए हमारा उससे विरोध है। अमरीका पाकिस्तान को बार-बार शस्त्रा-स्त्रों से लैस करता रहा जिस कारण पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया ताकि हम अपने डेवलपमेंट के काम को छोड़कर आर्मामेंट के काम में जुट जायें।

आज भी अमरीका, यूरोप के मुल्क इसलिए खिलाफ हैं कि अगर भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व की सरकार रहेगी और साइंस और टैक्नोलोजी को प्राथमिकता दे कर अगर अपने मुल्क का ग्रोथ रेट बढ़ाते रहेंगे तो आने वाले जमाने में 21वी शताब्दी में हिन्दुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली देश बन जाएगा। हिन्दुस्तान के पेट में आज दुनिया की सारी सम्पदा मौजूद है। रत्नगर्भ, इस धरती के पेट में दुनिया का शक्तिशाली देश बनने की क्षमता है। इसलिए यूरोप साम्राज्यवादी मुल्क हमारे विरोधी हैं। अभी हमारे देश में सोलर इनर्जी पर रिसर्च चल रहा है जिससे पूरे यूरोप में तहलका मचा हुआ है। अगर हिन्दुस्तान ने सोलर से बिजली बनाना सीख लिया तो यूरोप के मुल्क चूंकि ठण्डे हैं, यूरोप और अमरीका में जितना सूरज मिलता है उतना सूरज अकेले हिन्दुस्तान में मिलता है, तो हिन्दुस्तान न केवल अमरीका और रूस बल्कि इससे भी ज्यादा ताकतवर होकर दुनिया में बढ़ेगा। इसलिए अमरीका तथा दूसरे मुल्क हमारी एटोमिक, साइंस और टैक्नोलोजी नीति के विरोधी है। मुझे विश्वास है कि देश के विरोधी दल वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए, परिस्थितियों के अनुकूल जबकि हमारी सीमाओं पर दुश्मनों की सेनायें बैठी हुई हैं, सुपर पावर्स हिन्दमहासागर में न्यूक्लियर मिजाइल्ज के साथ पड़ी हुई हैं, हिन्दुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ देश से गरीबी हटाने का सवाल है दूसरी तरफ हमारे मुल्क को शक्तिशाली बनाने का सवाल है तो देश की नेता ने कहा है:

"I want to make India a strong, self-reliant socialist India. For that, a concerted, united, and tremendous national effort is needed. I want the cooperation of all the

[श्री कल्पनाथ राय]

political parties to build up a strong India."

मैं चाहता हूं कि आप श्रीमती इंदिरा गांधी की साइंस और टैकनोलोजी की नीतियों का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय सहयोग; राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर पापुलेशन की समस्या, गरीबी को दूर करने के सवाल पर विचार करें ताकि हम आने वाले समय में शक्तिशाली भारत का निर्माण करें और अतीत को सामने रख कर भविष्य के सुहाने दिन का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।

SHRI VIJAY N. PATIL: Mr. Vice-Chairman, Sir, while appreciating the claim of the State of Bihar for sufficient atomic energy for the development of industry and agriculture, I would like to state that the Atomic Energy Act of 1962 is sufficient to cover all aspects of development of atomic energy or erection of atomic power plants. There is no necessity for a separate Bill like this or a separate authority. Moreover, all the development that has taken place in the field of atomic energy is in the Central sector, as mentioned by Shri Kalpnath Rai. A lot of research is also involved in the field of atomic energy. So, a separate State subject cannot deal with all this and hence, since the beginning, it is in the Union List. Mr. Jha has rightly mentioned that the survey for uranium was done on an intensive scale in Bihar. The Uranium Corporation is also situated in Jaduguda. But unlike other materials uranium is not required to be transported in large quantities to the site of power plants as coal is required in the case of thermal power plants. We have already started power plants at Tarapur, Kalpakkam, Kota and in U.P. at Narora.

The contention of Mr. Jha that an atomic power plant will not require more than Rs. 10 crores of allocation, is not correct. For erection of one atomic power plant, to cite the example of Narora, about Rs. 300 crores are required and it is the policy of the Government that while considering distribution of power plants, whether hydro-electric, thermal or atomic, there has to be a radius of 800 kilometres. Hence, at this juncture, the demand raised by the Hon. Member cannot be considered. Furthermore, I would like to mention that the policy of the Government is for erection of thermal power plants *in situ* where coal is available and therefore, demand for a thermal power plant will be more appropriate in the case of Bihar State. So also, there is river Tista flowing through Sikkim which is having a very large potential of hydro-electric power generation, which once harnessed, Bihar and West Bengal will be bnefited, according to information.

The first atomic power plant, as Mr. Ramanand Yadav pointed out, was erected in Bombay. It was done keeping in view the industry's infrastructure existing there and also strategic point was the consideration at the time of erection.

I would also like to mention another important point that now the power plants that are coming up, are no solely dependent on uranium or enriched uranium, but heavy water is being utilised in them, as in Kota, and it will also be utilised in Narora. Of course, the anxiety expressed by the Hon. Members here for the industrial development of Bihar is well accepted, but it will not be proper to have a separate authority in one particular State for atomic energy and atomic power plants. So also, uranium is now being found in many other States and the research work, survey work is going on in Himachal Pradesh, in Shillong and so many other places. Then in whatever form uranium is found in Bihar, its process is very sophisticated. It is not used like coal directly into the power plants. There is a process before it is to be used for generating power. Hence the contention that it is locally available and that the power plant there will be economical, cannot be maintained.

Further, one Hon. Member mentioned it as a factory. I would like to state that in factories or in other industries, there is employment potential. But in atomic energy plants, there is not much of employment potential as visualised by the Hon. Member, who mentioned it as an industry. Of course, as I mentioned earlier, there is also the consideration of 800 kilometres radius. There is again a plan of the Government to have a grid system in all the States for providing sufficient power and whenever and wherever it is available, other States will be supplied. Bihar will not be left behind in that and we do recognise the fact that in spite of minerals being available in Bihar, it has remained industrially backward. But the steps taken for this purpose are to be from different angles and different aspects and, hence, I would like to point out to the Hon. Member that the legislation of the Central Government of 1962, is sufficient and it will be proper if he withdraws this Bill. I would request him to withdraw it.

श्री शिव चन्द्र झा : श्रीमन्, पहले तो मैं सब सदस्यों का, जिन्होंने इसमें भाग लिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जो सब शांतिपूर्वक सुनते रहे, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक में कम से कम बैठने की तो उन्होंने कृपा की—नहीं तो हल्ला होता है। लेकिन इतने अहम विषय में कम से कम बैठ करके सुनते रहे, इसके लिए धन्यवाद।

मंत्री महोदय ने भी जवाब दे दिया, यह एक औपचारिकता है, उस हिसाब से उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन केवल कि मंत्री जी की बातों की ओर जाऊं, जो बातें उन्होंने उठाई या जो अन्य सदस्यों ने बातें उठाई हैं, उनके मुतल्लिक मैं एक दो बातें कह देना चाहता हूं। हुक्मदेव यादव जी यहां पर नहीं है, उनका यह कहना था कि यह दक्षिण बिहार की ओर ही मैं ज्यादा ध्यान देता हूं, उत्तरी बिहार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं भी उत्तरी बिहार से आता हूं और उत्तरी बिहार पर ज्यादा ध्यान की जरूरत है, इसमें दो मत नहीं हैं। लेकिन विधेयक उस धातु के लिए उस चीज के लिए जो उसी दक्षिणी बिहार में जादूगुड़ा, सिंहभूमि में बहुत मिलती है, इसीलिए जो प्लांट बनाया जाएगा, तो वहीं पर जहां की रा-मैटेरियल्ज अवैलेबल हैं। इसीलिए अटामिक प्लांट के लिए जादूगुड़ा, सिंहभूमि में उपयुक्त स्थान है उत्तरी बिहार नहीं हो सकता है।

आप जानते हैं कि जो आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जो जमशेदजी नौशेरवानजी ने खोली, वे चाहते तो बहुत थे—लेकिन क्योंकि रा-मैटिरियल वहा पर थे, इसलिए—अब यह लम्बी कहानी है, पिछली दफा कह चुका हूं कि कैसे जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा ने इस गांव सांक्ची को चुना।

इसलिए यूरेनियम को लेकर दक्षिणी बिहार इलाका उपयुक्त होता है और वहीं पर यह हो सकता है। उत्तरी बिहार में उपयुक्त नहीं होता है। जहां तक उत्तरी बिहार के और उद्योगों की बात है, रामानन्द यादव जी बोले है, यह बात ठीक है कि उस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह तो मंत्री जी और सरकार का काम है और उस पर समय पड़ने पर विधेयक लाया जाएगा।

हमारे यह नौजवान साथी, यहां से उठ कर उधर चले गए और एक जमाना था जब वे सही रास्ते पर थे—कुछ साल से दूसरे रास्ते पर चले गए हैं. उनकी यह बात—जितनी बातें थीं एक इस विधेयक की—एक तरह से मैं कहूंगा कि औचित्य को काटा गया है और 1961 62 का जो है, उसके मुताबिक हो रहा है और होगा, यह एक जनरल बात है। लेकिन वहां पर अटामिक प्लांट जादुगुड़ा

[श्री शिव चन्द्र झा]

में न हो बिहार में, इस तरह की बात भी उन्होंने नहीं की ।

दूसरी बातें कि जनता सरकार में क्या हुआ, तारापुर के लिए यूरेनियम नहीं आ सका, यूरेनियम जनता सरकार नहीं ले आ सकी—फिर जब से मौजूदा प्रधान मंत्री आई हैं, तब से यूरेनियम बिलकुल एक धाराप्रवाह आता, शिपमैंट के बाद शिपमैंट, यह बात इन्होंने रखी है. . . वह भी कहानी हम जानते हैं कि किस तरह से आता है । लिखा-पढ़ी हो रही है, प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहा है । लेकिन अभी तक कोटा बाकी है ? अमरीका के साथ 1963 का ऐग्रीमेंट, अभी तक वह बाकी है, पूरा नहीं हो पाया है । जो नया अमरीकी शासन वहां आया है वह और भी सैबोटाज करने के लिए तैयार है और देखना है किस तरह से सैबोटाज करता है । कहने का मतलब यह है कि हम अभी तक डिपेंडेंट है इस मामले में । लेकिन एक बात जो थी उन के भाषण में, पीसफुल शांतिमय इस्तेमाल के लिए, इस में भी दो मत नहीं है । भारत जो एटामिक शक्ति का इस्तेमाल चाहता है वह इसलिए नहीं कि हम मैदान में जाकर उसकी मार दिखाएं । हम दुनिया को दिखाने आए हैं, जैसा 16 फरवरी को हुआ, यह एटामिक पावर अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि कृषि में क्रांति लाने के लिए और दवाओं में और दूसरे प्रयोग में इस्तेमाल करना चाहते हैं । भारत की जनता जैसी गरीब कही जाती है वह गरीब नहीं है । जो मैंने पहले भी कहा भारत की जनता गरीब बनाई गई अव्यवस्था की वजह से। उनको आगे लाना है, दुनिया के और मुल्कों के कदमों में भारत को आगे बढ़ना है । इसलिए हम हड़प्पा और मोहिंन-जोदड़ों की टैकनीक से काम नहीं कर सकते, इसमें दो मत नहीं, और हम विश्वास नहीं करते कि हड़प्पा और मोहिंजोदड़ो हमारे काम आएगी । हम चाहते हैं आधुनिकतम टैकनीकल नोहाऊ इस्तेमाल किया जाए । खेत के टुकड़े कितने ही छोटे हों लेकिन साइंटिफिक तरीके अप-टू-डेट इस्तेमाल किए जाएं । इसलिए एटामिक इनर्जी की बात आ जाती है, शांतिमय तरीकों से इसका इस्तेमाल हो और उन सब क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो । हमें इसका ध्यान देना है ताकि हम आगे बढ़ सकें और इसलिए जरूरी है कि जो यूरेनियम है उसका ठीक से इस्तेमाल हो । भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं । उन को सब पता है कि बिहार के बारे में जब मुख्तसर में उन्हों-ने समर्थन किया । बहुत अहम बात यह है कि इसकी उपयोगिता वहां पर है । मैं उन को धन्यवाद देता हूं । अब मंत्री जी का कहना है कि 1961–62 का जो ऐक्ट बना हुआ है उन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं । मैं उन से जानना चाहता हूं इस बारे में कहां-कहां सर्वे किया गया ? उसको टैप करने के लिए भी क्या कोई यूनिट्स जादूगुडा, सिंहभूमि में है या नहीं हैं ? या कि सारा आप टेलीफोन से या टेलिस्कोप बम्बई में लगा-कर ही यह सब करते हैं, या दूसरी जगहों से करते हैं। मेरे कहने का मतलब उपसभाध्यक्ष महोदय यह है कि कुछ तो वहां पर सर्वे किया जाता, छानबीन की जाती, जो कुछ भी वहां से निकाला जा सकता है । एक यूनिट का स्ट्रक्चर वहां पर है बिहार में और यदि वह बात नहीं है तो मंत्री जी कह दें नहीं है । अफसोस कि हम सिर्फ टेलीफोन से बात करते हैं और बाइनाक्यूलर लगा कर देखते हैं । तो वहां एक यूनिट का स्ट्रक्चर मौजूद है । मैं कहना चाहता हूं, यह जो स्ट्रक्-चर है इस को थोड़ा सा आप बड़ा बना दें । आज आप नहीं भी बनाएंगे, इस बात को नहीं भी कबूल करेंगे, लेकिन

कल आप को बनाना ही होगा । और आप बनाएंगे, इसी सदन से आप पास कराएंगे । इस विधेयक के मार्फत मैं यही चाहता हूं कि अभी जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बड़ा कर दें । स्ट्रक्चर नहीं है, सो बात नहीं है । मंत्री जी ने पुराने इतिहास को ठीक से कहा कि नहीं कहा, लेकिन यह प्रधान मंत्री जी का जवाब है :

An amount of Rs. 220 lakh is proposed tc be spent in Bihar for this survey, etc. etc. And these deposits at Jaduguda are being commercially exploited by the Uranium Corporation of India Limited which is a public sector undertaking under the Department of Atomic Energy.

4 P.M.

प्रधान मंत्री का जवाब है, और भी दूसरे जवाब हैं । पब्लिक अंडरटेकिंग यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया की यूनिट जादूगुडा में है । पैसे नहीं खर्च किये जाते, ऐसा नहीं है । 220 लाख की बात हुई । आप नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होता, कुछ खर्च नहीं होता । स्ट्रक्चर वहां पर है, यूनिट है, आप के लोग वहां काम करते हैं । मेरी दरखास्त सदन से और मंत्री महोदय से है कि इसको थोड़ा और बढ़ावें इस स्ट्रक्चर को फुल-फ्लेज्ड बनावें ।

आप ने बात उठाई पैसे की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की । यह दलील ऐसी दलील है जिस के जवाब में बहुत सी बातें आ जाती हैं । पैसा आपके पास नहीं है ऐसी बात नहीं, यह भी मैं कहना चाहता हूं । सवाल है कि आप के पास विल टु-डु की कमी है । यदि यह फैसला आप कर लेते हैं तो पैसा भी आप को मिल जायेगा । छोटा सा उदाहरण । 16 फरवरी के लिए पैसा कहां से आ गया ? 16 फरवरी को जो तमाशा हुआ उसके लिए कहां से पैसा आया ? उसके लिए भारत गरीब नहीं है ? उसके लि'! भारत की 48 प्रतिशत जनता गरीब नहीं है । कितना भी खर्चा हुआ 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़—मैंने तो 200 करोड की बात कही थी । यह नहीं है कि आप के पास पैसा न हो । आपके पास विल की कमी है, इच्छाशक्ति की कमी है । यह इच्छाशक्ति आप बना लेंगे तो भारत की भूमि में उतनी दौलत है, भारत के समाज में उतना धन है जो धन आपको मिलेगा और फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एटामिक प्लान्ट तो क्या हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों में आप कई बना सकते हैं । आप कहेंगे कहां से आयेगा । थोड़ी सी मुस्तैदी और दिल की बुलन्दी की जरूरत है । इनकम सीलिंग आप करते नहीं एक और दस के अनुपात में । आप समाजवाद का ढोंग करते हैं । आप समाजवाद की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं तो इनकम सीलिंग की बात भी गला फाड़ कर करो । यह तफरके जो समाज के हैं उनको दूर करने के लिए बुलन्दी चाहिए, एक ठोस कदम चाहिए । आप इनकम सीलिंग लगावें 1 और 10 के अनुपात में तो कितना पैसा मिल जायेगा ? एक हजार करोड़ रुपया प्रति साल आयेगा । अध्यक्ष महोदय, टैक्स ईवेजन की बात होती है । उसको रोकने से पैसा आयेगा । सवाल है कि आपका इरादा नहीं हैं । क्यों नहीं कहते कि हम बिहार को नजरन्दाज करना चाहते है, हम बिहार को इगनोर करना चाहते हैं इसलिए कि बिहार शुरू से ही बगावती रहा है । अंग्रेजी साम्राज्यवाद का मुकाबला बिहार ने किया। '42 में—गांधी जी के चम्पारन को छोड़ दीजिये—बिहार आगे रहा है । फिर '74 से लोकनायक के नेतृत्व में बिहार आगे रहा है । अब आप को लगता है फिर फिज़ा बन रही है, फिर वह वातावरण बिहार से शुरू न हो जाये । आपकी नीयत इगनोर करने की है । बिहार पिछड़ा रहा है, पर-केपिटा इनकम लोअर रही है । सारी योजनाओं को उलट कर आप देखिये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पांचवीं, छठी । छठी योजना में आप क्या करने जा रहे हैं । वायस चेयरमैन महोदय, पैसे की कमी देश में नहीं है । यह बेबुनियाद बात है । मैं उन की तरफ से उनकी वकालत कर सकता हूं ।

[श्री शिव चन्द्र झा]

ये फैसला करें, कल इन के पास पैसा हो जायेगा ये फैसला नहीं करना चाहते। बुनियादी बात यह है और यह इस लिए नहीं करना चाहते क्योंकि बिहार को पिछड़ा बनाये रखना चाहते हैं। खुद प्रधान मंत्री यहां विराजमान होतीं, विषय उनका है। मैं अभी भी दावत देता हूं वह आ जाये और जो मुझे कहना होगा उनके सामने कह दूंगा। तो बिहार को यह पिछड़ा ही रखना चाहते है। पैसे की कमी की वजह से नहीं बल्कि उनकी नीयत ठीक नही है इसलिये। बराबरी के आधार पर उसको जगह नही देना चाहिए। उनकी नीयत ही दूसरी है। आप जब वकालत करते हैं तो कहते है कि हम इस बिल को वापस लें। मैं जानता हूं कि आपकी ताकत है डिवीजन में, और यह सारा झमेला मैं चौथी लोक सभा से देखता आ रहा हूं। इस ताकत के बल पर भले ही आप इस विधेयक को पास न होने दें, लेकिन इसकी अहमियत से आप इन्कार नही कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप मेरे कहने के बाद अपनी बातों पर फिर गौर करें। आप कहें कि मै इसका पूरा सर्वे कराऊंगा। मेरे आंकड़े 1978 के हैं। मैंने उसमें बताया कि इतना पैसा लगेगा। आप को इसका सर्वे कराने में कि यह प्लान्ट बने बिहार में और उसका नकशा खींचने में कौन सी दिक्कत पेश आ रही है। मैं फिर दोहराता हूं कि आपके लोग वहां काम करते है और इसके मुताल्लिक आपको कोई नया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको यहां से आदेश जारी करना होगा कि इस का जरा पता चला लीजिए कि एटामिक प्लान्ट की वहां कितनी फिजिबिलिटी है और उसमें कितना पैसा लगेगा। एक मिनट में पता लग जायगा यदि उनकी नीयत साफ होगी तो। और मैं चाहता हूं कि आप बिहार का औद्योगीकरण करें। श्री रामानन्द यादव जी ने कहा, आप देखें कि एच० एम० टी०को कहां-कहां ले जाया जा रहा है। पटना के पास एक हिन्द साइकिल फैक्टरी होने वाली थी। वह भी वहां नहीं दी गयी है। तो बुनियादी बात यह है कि यह नहीं चाहते हैं कि किसी तेज रफ्तार के साथ बिहार का औद्योगिकरण हो। हर तरह से उसकी उपेक्षा हो रही है। अभी हम और राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे हैं और बराबरी के आधार पर हम को नही लाया जा रहा है और इस के लिये ही भाषा को लेकर वहां एक बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है। यह उन की बेचैनी प्रतिबिंबित होती है भाषा के आन्दोलन में और ऊपर से ऐसा मालूम होता है कि वह आन्दोलन उर्दू के खिलाफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बल्कि यह आन्दोलन वहां इस लिये जोर पकड़ रहा है कि एक दूसरी भाषा बिहार की मैथिली है और जिस को संविधान में मान्यता नहीं दी गयी है और बिहारवासी उस समय तक दम नही लेंगे जब तक कि उसको संविधान में मान्यता नहीं मिल जाती। बिहार की आधी आबादी, उससे ज्यादा आबादी मैथिली बोलती है। साहित्य अकादमी ने उसको मान्यता दे दी है, लेकिन क्या वजह है कि सरकार उसको संविधान में स्थान नहीं देती। और इसी लिये वहां की जनता तूफानी होती जा रही है और इसलिये आप हर तरह से बिहार को इग्नोर कर रहे हैं। वहां एक आग सुलग रही है। अभी वह चिंगारी के रूप में है और कल दावानल के रूप में भड़कने वाली है। आपके लिये वह एक समस्या हो जायेगी। जैसे कि आज आसाम की एक समस्या है और जैसे गुजरात आप को आज चुनौती दे रहा है, गुजरात आप को बुला रहा है और आप के लिये सिरदर्द हो रहा है और जैसे दूसरे इलाके अशान्त है उसी प्रकार बिहार भी आपके लिये एक समस्या हो जायगा। इसलिये मंत्री जी ठंडे दिमाग से इस पर विचार करें, जोश में आकर नहीं बल्कि होश में आकर विचार करें और जो बातें आप ने कही हैं उन पर आप फिर से विचार करें, गौर करें और यह आश्वासन दें। मै मानता हूं कि काम करने में वक्त लगता है और वह एक तरीके से ही होता है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार ने यह नहीं किया। मैं मानता हूं कि

जनता सरकार के दर्शन में कोई दोष नहीं था। न उसकी नीति, न फिलासफी थी। लेकिन जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है इसकी वजह से काम न हो सका जितना होना चाहिए था और आपके यहां भी वही काम नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए थे। कदम कदम पर ब्यूरोक्रेसी आपको घुन के रूप में चाहे यह सदन हो या कहीं हो, मैं यहां से उदाहरण लेकर आपको कहना चाहता हूं कि अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी की बहानेबाजी यह ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को और हमारे प्रशासन की मशीनरी को खा रही है। इसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा है। तो आप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, असम्भव बात नहीं है। आप इसका सर्वे कराइये, इसमें कितना खर्चा होगा यह सर्वे कराइये। 50 हजार, 1 लाख कितना लगेगा। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जहां 200 करोड़ रुपये 16 तारीख को खर्चा हुआ तो 50 लाख या 1 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है। इसीलिए आप सर्वे कराइये ताकि बिहार की जनता को तसल्ली होगी दिल्ली की सरकार हमारे लिए कुछ करना चहाती है और बाबू जगन्नाथ मिश्र पर आप बैन करते है। उन्हीं की बदौलत आप वहां पर कायम है। वे आप के साथ हैं। जिनको लेकर आप डूब जायेंगे वहां पर। आपका काम है कि आप जनता की अदालत में जायें और उनके लिए काम करें।

मैथिली की मान्यता की बात मैंने कही। वह भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह विधेयक मेरा आ रहा है। लेकिन यह अटामिक पावर के लिए आप काम करें ताकि बिहार की जनता समझे कि केन्द्र सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। इन्होंने कहा कि जबसे 1980 में नई सरकार आई है, काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि नौजवानो देख लो, नेशनल सेक्यूरिटी ऐक्ट आ गया है, कहां भूले जाते हो। अगर हमारे साथ रहे तो समझोगे। नहीं तो कल तुम बन्द हो जाओगे। प्रधान मंत्री जी तुमको जानती हैं कि तुम एम० एस० पी० के आदमी रहे हो। एक एम० एस० पी० मैन इज आलवेज एम० एस० पी० मैन। तुम्हारे बारे में वह जानती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, नेशनल सेक्यूरिटी ऐक्ट क्या है? इमरजेंसी नहीं है, फिर इमरजेंसी नहीं बुलाई जा रही है, फिर वह फिजां नहीं बन रही है? हम लोग तैयार हैं। 23 महीने मैं मीसा में रहा 18 महीने इमरजेंसी में और 5 महीने इसके कब्ल मीसा में, 23 महीने बन्द रहा और मैं सबके साथ तैयार हूं। अगर इमरजेंसी दूसरी बार दोहराई जाएगी और उसी प्रकार जनतंत्र का गला घोंटा जाएगा तो भारत की जनता ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। 1979-80 में जनता ने जवाब दिया, फिर आने वाले चुनावों में फिर जवाब देगी। 1977 में तो उत्तरी भारत से सफाया हुआ इस बार दक्षिणी भारत से भी सफाया हो जाएगा।

इसीलिए यदि आपको वह दिन न देखना हो, सत्ता यहां बरकरार रखनी हो तो हम लोगों की यही भावना है कि समाजवादी समाज बने। गांधी, जयप्रकाश लोकनायाक तथा डा० लोहिया के सिद्धान्तों के अनुसार नया समाजवादी समाज बने जिसकी तरफ से बनता है उसमें हमें खुशी होगी। लेकिन वह यदि नहीं बनता हो और गद्दी पर आसीन होकर गद्दी शास्त्र में आप विश्वास करते हो, उसके नाम पर समाजवाद का नाम लेते हो तो जनता इसको भी पहचानती है। इसीलिए साउथ बिहार की जनता की सेवा के लिए, उनकी भलाई के लिए और कम कामों के अलावा यह काम भी करें। यह काम कुछ टेक्किनल जरूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बातों को भी मद्देनज़र रखते हुए आप इस विधेयक को ऐक्सेप्ट करें। बाकी आर्गुमेंट की बात नहीं है, मै तो कहूंगा कि आश्वासन आप दें कि इसकी फिजिबिलिटी का पता लगायेंगे कि कितना खर्चा लगेगा। कहां तक इसकी संभावना है। बिना सोचे एक असेसमेंट न बना लें कि

[श्री शिव चन्द्र झा]

हमने एक बार जो कह दिया हम पीछे नहीं हटेंगे, इसको आप प्रेस्टिज इश्यू न बना लें। ऐसी बात न रखें। मैं तो कहूंगा कि आप इसे ऐक्सेप्ट कर लें। आप कहेंगे कि हमें ग्रीन सिगनल नहीं मिला, हैड आफिस से ग्रीन सिगनल नही मिला इसलिये मैं नहीं मान रहा हूं। सिगनल जब मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा। यह अलग बात है। मेरा कहना है कि आपने जो दलील यहां रखी है उसमें कोई जान नहीं है। उसमें कोई दम नहीं है। आप यह बतायें कि भारत सरकार अटोमिक प्लांट लगाने के लिये कोई सर्वे कर रही है या नहीं। यदि नही कर रही हैं तो आप शुरू करवा दें। रिसोर्सेज की बात बाद में आएगी। वह सब कुछ हो जाएगा। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं फिर सभी को धन्यवाद देता हूं। जो बोले उनको भी, जो चुप रहे उनको भी धन्यवाद देता हूं। जो सुनते रहे है उनको भी धन्यवाद देता हूं। मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि वह हमें इस बात का आश्वासन दे दें कि वह सर्वे करा रहे हैं। हम यहां कनफ्रनटेशन के लिये नहीं आए हैं हम टकराव के लियें यहां नहीं आए हैं। हम काम करने के लिये यहां आए हैं। हमें काम करने की भावना हमारे नेताओं ने सिखाई है। अननोन, अनहर्ड, अनसंग जो कहा गया है उस रूप में हम लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसको आप करेंगे तो इससे आपको ही यश मिलेगा। इसलिये आप आश्वासन दे दें कि हम इसका सर्वे करायेंगे कि आटोमिक प्लांट कहां लगेगा इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को मान ले और सदन से पास करने के लिये कहें।

श्री विजय एन० पाटिल : आपने जो सुझाव सर्वे के बारे में दिया है मैं उस बारे में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान भर मे सर्वे कराया जा रहा है। यह कंटीन्युअस प्रोसैस है। इसमे बिहार को भी ध्यान में रखा जाएगा इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से बिल को विदड्रा करने के लिये रिक्वेस्ट करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री विश्वम्भर नाथ पांडे) : आप बिल वापस ले रहे हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा : इन्होंने जो जवाब दिया है मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह बिहार में अटोमिक प्लांट के ख्याल से बताएं कि वह सर्वे करायेगे या नहीं। दूसरी बातें कहने से काम नही चलेगा।

श्री कल्पनाथ राय : झा साहब आप विद्ड्रा कर लीजिए।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं नहीं करता।

उपसभाध्यक्ष (श्री विश्म्भर नाथ पांडे): क्योंकि विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य अपना विधेयक प्रैस कर रहे हैं, I am putting it to vote.

The question is:

"That the Bill to provide for the formation of an Authority for the purpose of setting up an atomic plant in the State of Bihar and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE): Now, we go to the next Bill. Shri F. M. Khan. Not present. Shri Murasoli Maran. He is also not present. Shri Bhupesh Gupta. He is also not present. Shri Shiva Chandra Jha.

—

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1978

(to amend the Eighth Schedule)

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी यह दरखास्त है कि मेरा यह जो नं० 5 पर कांस्टिट्यूशन एमेंडमेन्ट बिल है उसकी जगह पर